

to refrain from using the stream water for a day and checks showed that within two hours the caustic level in the water had come down within passable limits. Thus, no health hazard was caused owing to the spillage.

(b) Neither aluminium power nor aluminium was used to stop the spillage.

(c) to (e). Do not arise.

**Language of Mortgage Deed on property for housing loans for L.I.C. employees**

793. SHRI SUNIL MAITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the L.I.C. insists on Mortgage Deed in English Language on the property for grant of housing loan even to its permanent employees; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGABHAI BAROT): (a) and (b). The information is being gathered and would be laid on the Table of the House as soon as it is available.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा  
अग्रिम राशि:

794. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन राज्यों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा-अग्रिम राशि देने का विचार है जो बढ़ से प्रभावित हैं जिसके परिणाम-स्वरूप जान माल की बहुत क्षति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक दे दिया जाएगा ; और

(ग) क्या सरकार का इस समय बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए बढ़ अग्रिम राशि रु० 500/- से बढ़ा कर रु० 1000/- करने और उसके 50 किस्तों में वसूली के आदेश जारी करने का विचार है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख). सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 247 के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्षों को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन अराजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी चल अथवा अचल सम्पत्ति बढ़ से प्रभावित अथवा क्षतिग्रस्त हो गई है, तीन महीने का अग्रिम वेतन अथवा 500/- रुपये, इन में से जो भी कम हो, मंजूर करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, बशर्ते कि संबंधित राज्य की सरकार ने, जहां पर बढ़ आई है, उन क्षेत्रों को बढ़ से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया हो, तथा उसने अपने कर्म-चारियों को वित्तीय सहायता भी दी हो। तदनुसार सरकार के कोई औपचारिक आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी संबन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बढ़ से प्रभावित क्षेत्रों तथा उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई वित्तीय सहायता की सूचना दें।

(ग) जी नहीं। चूंकि जहां पर बढ़ आती है वहां के सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा राज्य सरकारें आम जनता को, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, सहायता देती हैं इसलिए अग्रिम की मात्रा में वृद्धि करना उचित नहीं समझा गया।